नईदुनिया

उरुग्वे में एवियन इन्फ्लूएंजा की दस्तक, एच5 वायरस मिलने पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित

मोंटेवीडियो

उरुग्वे में घरेलू पोल्ट्री में अत्यधिक रोगजनक 5 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस मिलने के बाद सरकार ने देशभर में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। अधिकारियों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पोल्ट्री की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाने के साथ पक्षियों से जुड़े मेलों, नीलामी और सार्वजनिक प्रदर्शनियों पर भी रोक लगा दी है।

तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू के मुताबिक पशुधन, कृषि और मत्स्य पालन मंत्रालय के तहत पशुधन सेवा महानिदेशालय ने दक्षिण-पश्चिमी कोलोनिया क्षेत्र में एवियन इन्फ्लूएंजा के संक्रमण की पुष्टि की। अधिकारियों के मुताबिक, इलाके में पक्षियों की मौत के बाद जांच शुरू की गई थी। शुरुआती रैपिड टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाद में सरकारी प्रयोगशाला की जांच में ।।5 वायरस की मौजूदगी सामने आई।

आपातकालीन आदेश के तहत प्रभावित क्षेत्र में प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। बिना व्यावसायिक उद्देश्य के पाले जाने वाले पक्षियों की घरेलू आवाजाही पर रोक लगाई गई है। हालांकि, सरकारी पोल्ट्री निगरानी प्रणाली में पंजीकृत पक्षियों को कुछ परिस्थितियों में इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

वहीं, अधिकारियों ने घरों में खुले तौर पर घूमने वाले पक्षियों को बंद और ढकी हुई जगहों में रखने का निर्देश दिया है, ताकि उनका संपर्क जंगली पक्षियों से न हो। स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रभावित स्थान पर संक्रमित या संपर्क में आए पक्षियों को मारने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही संभावित रूप से दूषित स्थानों और सामग्री की व्यापक सफाई तथा कीटाणुशोधन किया जा रहा है। पोल्ट्री उत्पादकों को कड़े जैव-सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। इनमें बिना अनुमति लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक, जंगली पक्षियों से पानी और चारे को सुरक्षित रखना तथा नियमित कीटाणुशोधन जैसे कदम शामिल हैं। उरुग्वे के अधिकारियों ने कहा है कि पोल्ट्री का मांस और अंडे खाने से आम तौर पर इंसानों के लिए स्वास्थ्य जोखिम नहीं है, बशर्ते उन्हें उचित तरीके से संभाला और पकाया जाए। हालांकि, कृषि और स्वास्थ्य टीमें उन लोगों की निगरानी कर रही हैं, जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आए हैं। एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) का एक अत्यधिक रोगजनक उपप्रकार है, जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। संक्रमित पक्षियों के निकट संपर्क में आने पर यह मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। हालांकि, मनुष्य से मनुष्य में इसके लगातार प्रसार का प्रमाण नहीं मिला है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बीमार या मृत पक्षियों को सीधे न छुएं और ऐसे मामलों की सूचना संबंधित स्वास्थ्य या पशु चिकित्सा अधिकारियों को दें।

न्यूज़ ब्रीफ

व्यापार घाटा घटाने के लिए भारत के साथ निर्यात बढ़ाएगी ढाका सरकार : वाणिज्य मंत्री मुक्तादिर

ढाका। बांग्लादेश सरकार भारत और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए किसी एक देश पर केंद्रित रणनीति अपनाने के बजाय देश की कुल निर्यात क्षमता बढ़ाने पर जोर देगी।

वाणिज्य मंत्री खांडकर अब्दुल मुक्तादिर ने संसद में यह जानकारी दी। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संगबाद संस्था (बीएसएस) के मुताबिक, मंत्री ने जातीय संसद में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान विपक्षी जमात-ए-इस्लामी के सांसद एम. अब्दुल बातेन के पूरक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारत और चीन के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा काफी बड़ा है, लेकिन इसे केवल किसी एक देश से जुड़ी समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें किसी एक देश पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी कुल निर्यात क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। मुक्तादिर ने बताया कि सरकार ने निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं वाले कई क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें चमड़ा, जूट, जहाज निर्माण, हल्का इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में अनुकूल नीतियां बनाने और नए निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, ऐसे उद्योगों को भी विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो अभी अपनी पूरी निर्यात क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। वाणिज्य मंत्री के अनुसार, बांग्लादेश और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य करीब 12.7 अरब अमेरिकी डालर है। इसमें बांग्लादेश भारत को लगभग 1.89 अरब डालर का सामान निर्यात करता है, जबकि भारत से होने वाला आयात इससे काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में और बढ़ा है। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में बांग्लादेशी उत्पादों के निर्यात की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय पक्ष की ओर से कुछ प्रतिबंध भी हैं।

पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर कर दिया ध्वस्त, बवाल हुआ तो सरकार ने कहा- बारिश की वजह से गिरा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित करीब 100 से 125 साल पुराने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के ध्वस्त होने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक विवाद गहरा गया है।

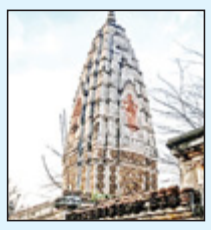

मंदिर के गिराए जाने की खबर सामने आने के बाद भारत ने इस घटना पर कड़ी चिंता व्यक्त की है और इसे अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थल के खिलाफ एक निंदनीय कार्रवाई बताया है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है। स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों का दावा है कि नरोवाल के सिराज गांव में स्थित इस मंदिर को धार्मिक कट्टरपंथियों के एक समूह ने जानबूझकर गिराया। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर कब्जा कर पास स्थित एक मदरसे का विस्तार करने की कोशिश की गई थी। दूसरी ओर, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मंदिर को किसी समूह ने जानबूझकर नष्ट नहीं किया, बल्कि 21 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के कारण इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाकिस्तान का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों ने बारिश से हुए नुकसान का सर्वेक्षण किया है और मंदिर की बहाली के लिए आवश्यक कदम शुरू कर दिए गए हैं। भारत ने इस घटना पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के नरोवाल स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर के नष्ट होने की खबरों पर तत्काल प्रतिक्रिया दी।

ट्रंप को झटका कांग्रेस का कार्यकाल दो हफ्ते घटाया

वाशिंगटन। अमेरिका की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों उथल-पुथल जारी है, जहां मध्यावधि चुनावों की बढ़ती चिंताओं के कारण रिपब्लिकन पार्टी नेतृत्व ने प्रतिनिधि सभा (अमेरिकी कांग्रेस) के आखिरी दो हफ्तों के कार्यकाल को रद्द कर दिया है।

इस फैसले के परिणामस्वरूप, सितंबर के लिए तय विधायी कैलेंडर काफी छोटा हो गया है, जिससे सांसदों को अपने-अपने गृह क्षेत्रों में लौटकर आगामी मध्यावधि चुनावों के लिए मतदाताओं से जुड़ने का अधिक समय मिल सके। यह निर्णय रिपब्लिकन सांसदों के उस दबाव के बाद आया है, जिसमें वे अपने चुनावी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वाशिंगटन छोड़ने की मांग कर रहे थे। इस घोषणा के बाद, सभी सांसद 17 सितंबर से अपने-अपने गृह जिलों में लौट जाएंगे और सीधे नवंबर में मध्यावधि चुनावों के बाद ही सदन में वापस आएंगे। हालांकि, यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सदन को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। इस कदम को सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन के लिए झटका नहीं माना जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के सत्र में न होने पर भी राष्ट्रपति फैसले ले सकते हैं।

नेपाल बाढ़ : दस दिन बाद भी रसुवागढ़ी हाइड्रोपावर में नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम, 93 कर्मचारी हैं संपर्कविहीन

काठमांडू

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित रसुवा जिले में स्थित रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना के पावरहाउस की सुरंग में फंसे कर्मचारियों तक अब तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी है। सुरंग के भीतर करीब 12 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है, जबकि परियोजना में काम करने वाले 93 लोग अब भी संपर्कविहीन बताए जा रहे हैं।

परियोजना प्रबंधन के मुताबिक, बचाव अभियान के लिए जरूरी सभी उपकरण परियोजना स्थल तक नहीं पहुंचाए जा सके। रसुवागढ़ी हाइड्रोपावर कंपनी से संपर्कविहीन 93 कर्मचारियों की तलाश और बचाव अभियान लगातार जारी है।

कंपनी के अनुसार, संपर्क से बाहर लोगों में 51 नियमित कर्मचारी, एक संचालक, दो दैनिक मजदूर और तीन ठेकेदार कंपनियों के 39 कर्मचारी शामिल हैं। पावरहाउस की सुरंग में फंसे कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले सुरंग में जमा कीचड़ और मलबे को हटाना जरूरी है।

इसके लिए मिनी एक्स्कावेटर, 30 केवीए डीजल जनरेटर, सबमर्सिबल पंप और होज पाइप समेत आवश्यक उपकरण 2 अगस्त को ही नुवाकोट के मैथली आर्मी कैंप, बट्टार में पैक कर दिए गए थे। इन उपकरणों को धुन्चे के रास्ते परियोजना स्थल तक पहुंचाने की योजना थी।

नेपाली सेना की बचाव टीम ने जब पावरहाउस तक पहुंचने के लिए इलाके की रेकी की तो सामने आया कि पावरहाउस के पास नदी ने और अधिक कटाव कर दिया है। सेना के मुताबिक, भारी उपकरणों के साथ बड़े एमआई-17 हेलीकाप्टर को वहां उतारना संभव नहीं है।

इसके बाद कम क्षमता और कम वजन वाले जनरेटर की व्यवस्था की गई। मिनी एक्स्कावेटर और बड़े डीजल जनरेटर को छोड़कर बिजली से संबंधित अन्य उपकरण और जरूरी सामग्री धुन्चे तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन ये सामान अभी भी धुन्चे में ही रखा हुआ है।

पावरहाउस के बाहर लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए कंपनी ने नेपाल नेशनल माउंटेन गाइड एसोसिएशन से जुड़े अनुभवी राक क्लाइंबरों की टीम

को भी अभियान में उतारा है।

कंपनी ने 3 अगस्त को हिमालय समिट क्लब प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था। इसके तहत राक क्लाइंबरों को घट्टेखोला कैंप और आसपास के ऊंचे इलाकों में चार दिनों के लिए ग्राउंड सर्च के लिए तैनात किया गया है।

कंपनी के अनुसार, टीम फिलहाल टिमुरे में है और उसे एक अन्य हेलीकाप्टर से घट्टेखोला ले जाकर तलाशी अभियान चलाने की योजना है।

कंपनी ने कर्मचारियों और संपर्कविहीन कर्मचारियों के परिवार एवं रिश्तेदारों को बचाव अभियान की स्थिति की नियमित जानकारी देने के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के जरिए तलाशी और बचाव अभियान के दौरान सामने आने वाली जानकारी तथा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी साझा की जा रही है।

कंपनी के संचालक भी नियमित रूप से कार्यालय में मौजूद रहकर परिजनों को स्थिति की जानकारी देने की व्यवस्था कर रहे हैं।

खोज और बचाव अभियान के लिए आवश्यक समन्वय के उद्देश्य से नुवाकोट के बट्टार में एक वरिष्ठ इंजीनियर समेत दो लोगों को तैनात किया गया है। वहीं, रसुवा के धुन्चे में दो इंजीनियरों को तैयार रखा गया है। पावरहाउस में बचाव दल को बिजली कनेक्शन से जुड़े कार्यों में मदद देने के लिए एक इलेक्ट्रिकल ओवरसियर भी तैनात है। कंपनी के मुताबिक, धुन्चे में नेपाली सेना की विशेष बचाव टीम भी मौसम अनुकूल होने का इंतजार कर रही है। मौसम साफ होते ही टीम जरूरी उपकरणों के साथ पावरहाउस पहुंचकर बचाव अभियान में शामिल होगी। बाढ़ के 10 दिन बाद भी सुरंग तक पहुंचने में आ रही बाधाओं ने रेस्क्यू आपरेशन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अब सभी की नजर मौसम में सुधार और जरूरी भारी उपकरणों को परियोजना स्थल तक पहुंचाने पर है।

बोलीविया के सैन्य बेस में भीषण धमाका, करीब 10 लोगों की मौत और 62 घायल

ला पाज़

बोलीविया की राजधानी ला पाज़ से करीब 30 किलोमीटर दूर विआचा शहर में एक मिलिट्री बैरक में भीषण धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, धमाका उस इलाके में हुआ जहां आतिशबाजी का सामान रखा गया था।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, धमाका रक्षा मंत्रालय के आतिशबाजी के स्टाक में आग लगने के बाद हुआ। हालांकि, आग लगने और धमाके की वास्तविक वजह का अभी पता नहीं चल सका है। विआचा की स्वास्थ्य निदेशक रीटा नेब्रास्का ने स्थानीय मीडिया को बताया कि घटना में मृतकों की संख्या 10 से 15 तक पहुंच सकती है। उन्होंने बताया कि हादसे में 62 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 14 लोगों को ला पाज़ के अस्पतालों में भेजा गया है।

इनमें एक लड़की भी शामिल है, जो थर्ड-डिग्री बर्न यानी गंभीर रूप से झुलस गई है। पुलिस के मुताबिक, हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और आसपास के दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई घरों की खिड़कियां टूट गईं और कुछ इमारतों को ढांचागत नुकसान भी हुआ।

घटना के बाद मिलिट्री काम्प्लेक्स में एंबुलेंस, मेडिकल टीमें और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। राहतकर्मी घायलों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने और इलाके में हुए नुकसान का जायजा लेने में जुटे रहे। स्वास्थ्य निदेशक रीटा नेब्रास्का के अनुसार, दमकलकर्मियों ने घटनास्थल पर अभी भी गर्मी का स्रोत मौजूद होने की चेतावनी दी है। इससे दोबारा धमाका होने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों से घटनास्थल से कम से कम 150 मीटर दूर रहने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और धमाके के कारणों की जांच की जा रही है।

बोलीविया दक्षिण अमेरिका का एक स्थलरुद्ध देश है, जिसकी सीमाएं ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पैराग्वे से लगती हैं।

ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल से हमला

तेहरान। फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप के पास एक छोटे ईरानी तेल टैंकर को अमेरिकी सेना की मिसाइल ने निशाना बनाया। फिलहाल, इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू और ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तसनीम न्यूज़ के अनुसार, घटना खार्ग द्वीप से करीब छह नाटिकल मील दूर हुई। तसनीम ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि लंगर डाले हुए टैंकर पर अमेरिकी सेना की ओर से दागे गए करीब चार प्रोजेक्टाइल लगे। रिपोर्ट के मुताबिक, हमले के बाद टैंकर के क्रू मेंबर्स को जहाज से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई। स्थानीय सूत्रों ने दावा किया कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों की ओर से फिलहाल टैंकर को हुए नुकसान की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। संबंधित एजेंसियां घटना की परिस्थितियों और नुकसान की सीमा की जांच कर रही हैं। फिलहाल, अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस कथित मिसाइल हमले पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए टैंकर पर हमले से जुड़ी जानकारी को फिलहाल ईरानी मीडिया और स्थानीय सूत्रों के दावे के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रंप ने 9/11 की बरसी से पहले अल-कायदा से जुड़े लोगों पर से हटाया प्रतिबंध

वाशिंगटन

अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी की तैयारियों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक कथित फैसले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने अल-कायदा से जुड़े कई लोगों को अपनी नामित आतंकवादियों की सूची से हटा दिया है।

ईरान सरकार की अंतरराष्ट्रीय समाचार नेटवर्क प्रेस टीवी

ने ग्रे ज़ोन' की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सूची से हटाए गए लोगों में सीरिया में अल-कायदा की शाखा से जुड़े कमांडर, रिक्रूटर और फाइनेंसर शामिल हैं। इनमें सऊदी धर्मगुरु अब्दुल्ला मुहयसिनी का नाम भी बताया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुहयसिनी ने सीरिया में लड़ाकों की भर्ती और कट्टरपंथी गतिविधियों में भूमिका निभाई थी। उसका नाम कथित तौर पर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा (पूर्व में अबू मोहम्मद अल-जुलानी) के अनुरोध पर सूची से हटाया गया।

हालांकि, इस पूरे मामले से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। अल-जुलानी का अतीत अल-कायदा की सीरियाई शाखा अल-नुसरा से जुड़ा रहा है। बाद में संगठन ने अपना नाम बदलकर हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) कर लिया था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अबू सुलेमान अल-मुहाजिर, शफी सुल्तान मोहम्मद अल-

अजमी और अब्दुल समरेज़ जशारी समेत अन्य लोगों को भी अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटाया गया है।

अमेरिकी प्रशासन की ओर से इन सभी मामलों पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सूची से हटाने का आधार और उद्देश्य क्या था।

11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासन ने अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई शुरू की। बाद में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां इराक और सीरिया तक फैल गईं, जहां इस्लामिक स्टेट यानी दाएश (आईएसआईएस) के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। अल-कायदा से जुड़े बताए जा रहे लोगों पर प्रतिबंध हटाने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब अमेरिका 9/11 हमलों की 25वीं बरसी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इस फैसले को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों और विश्लेषकों के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, प्रतिबंध सूची में किसी व्यक्ति का नाम हटना अपने आप में उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों के खत्म होने का प्रमाण नहीं होता। इस मामले में अमेरिकी सरकार की आधिकारिक जानकारी और संबंधित दस्तावेजों से ही अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सेना भेजने से दक्षिण कोरिया ने किया इनकार, कहा-समीक्षा जारी

सियोल

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सैन्य बल भेजने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सरकार इस प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा कर रही है और किसी भी निर्णय से पहले देश की रक्षा तैयारियों तथा कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि यदि दक्षिण कोरिया होर्मुज़ में योगदान देने का फैसला करता है, तो वह जलडमरूमध्य में मुक्त और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सैन्य सहयोग कर सकता है। हालांकि, यह योगदान ऐसा होना चाहिए जिससे कोरियाई प्रायद्वीप पर दक्षिण कोरिया की रक्षा तैयारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें दावा किया गया था कि दक्षिण कोरियाई सरकार होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सैन्य बल भेजने की योजना पर संसद की मंजूरी लेने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों में काम्बैट सपोर्ट शिप समेत अन्य सैन्य संसाधनों की तैनाती की संभावना जताई गई थी।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकार की बातचीत अभी संसद की मंजूरी लेने के चरण तक नहीं पहुंची है और तैनाती को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि होर्मुज़ में सैन्य योगदान का मतलब केवल लड़ाकू सैनिकों की तैनाती नहीं है। सरकार गैर-लड़ाकू बल, खोज एवं बचाव दल तथा अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार कर रही है।

अधिकारी ने कहा कि सैन्य तैनाती को सीधे युद्ध या लड़ाई से जोड़ना जरूरी नहीं है। दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा स्थिति और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों की समीक्षा कर रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दक्षिण कोरिया पर होर्मुज़ जलडमरूमध्य में योगदान देने का दबाव बढ़ाया गया है। ट्रंप कई बार सियोल पर अमेरिकी अनुरोध को ठुकराने का आरोप लगा चुके हैं।

हालांकि, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कार्यालय ने उन अटकलों को खारिज किया कि होर्मुज़ में संभावित सैन्य तैनाती का मुद्दा सियोल और वाशिंगटन के बीच चल रही बातचीत में बड़ी बाधा बन गया है।

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच पिछले साल हुए बड़े टैरिफ समझौते के तहत आर्थिक और रक्षा संबंधी समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने माना कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि बातचीत में सेमीकंडक्टर से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। इसी बीच अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि ट्रंप प्रशासन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए एक विशेष और रणनीतिक टैरिफ नीति तैयार करने पर काम कर रहा है।

फिलहाल दक्षिण कोरिया का रुख यही है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी संभावित योगदान पर फैसला देश की सुरक्षा जरूरतों, कानूनी प्रक्रियाओं और रक्षा तैयारियों की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।